Mafia employees in Dhori area of Central Coalfied Limited

1989. SHRI SAMAR MUKHERJEE; Will the Minister of COAL be pleased to state;

(a) whether Government have received any complaints about 'Mafia employees in Dhori area of CCS amassing wealth at the cost of the company during the last three months; if so, the details of the facts;

(b) whether any probe has been made in this connection; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कोल इंडिया लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन किया जाना

1990. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री रणजीत सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला उद्योग की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1981 में कोल इंडिया लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन करने का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 1991 तक कई समितियां गठित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी समिति कब-कब गठित की गयी, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब-कब सौंपी तथा इन समितियों पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड़ा) : (क) से (घ) अगस्त, 1980 में श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की जांच करने और आंतरिक संसाधनों को जुटाने और उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए जाने के लिए गठित की गई थी। अन्य बातों के अलावा, समिति ने नवम्बर, 1980 में यह सुझाव दिया था कि कोल इंडिया लि० को०इं०लि०) का एक धारक कंपनी के रूप में परिसमापन कर दिया जाए और सहायक कंपनियां स्वतंत्र कंपिनयों के रूप में कार्य करें। समिति की इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने, सितम्बर, 1984 में डा० अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित के संबंध में जांच किये जाने के लिए एक समिति का गठन किया था। वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने और अन्य परिवर्तनों का सुझाव दिये जाने ताकि सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी दी जा सके। इस समिति ने दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सार्वजनिक उद्यमों के लिए धारक कंपनी ढांचा एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में एक उपयुक्त ढांचे का स्वरूप प्रदान करता है।

दिसम्बर, 1986 में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों की जिम्मेदारी तथा उनकी विद्यमान भूमिका की समीक्षा किए जाने का अध्ययन किए जाने का कार्य सौंपा गया था। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज ने अप्रैल, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।